रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 282] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 31, 2017/माघ 11, 1938
No. 282] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 31, 2017/MAGHA 11, 1938

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2017

का.आ. 313(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम,1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य-आबंटन) तीन सौ इकत्तीसवां संशोधन नियम, 2017 है।

(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम,1961 की द्वितीय अनुसूची में,-

(क) "सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय" शीर्षक के अधीन, "क. सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग" उप-शीर्षक के नीचे, प्रविष्टि 24 के पश्चात, निम्नलिखित प्रविष्टि अन्त:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"25. नीति आयोग द्वारा तैयार किए गए ढांचे और तंत्र के आधार पर अनुसूचित जाति उप-योजना की मानीटरी।";

(ख) "जनजातीय कार्य मंत्रालय" शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि 9 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अन्त:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"10. नीति आयोग द्वारा तैयार किए गए ढांचे और तंत्र के आधार पर जनजातीय उप-योजना की मानीटरी।";

(ग) "नीति आयोग (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था)" शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि 1 में, मद (i) के अधीन, उप-मद ड. के पश्चात्, निम्नलिखित उप-मद अन्त:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"ढ. (अ) अनुसूचित जाति उप-योजना तथा जनजातीय उप-योजना की मानीटरी के लिए ढांचा और तंत्र तैयार करना;

(आ) अनुसूचित जाति उप-योजना तथा जनजातीय उप-योजना का मूल्यांकन करना"।

प्रणब मुखर्जी

राष्ट्रपति

[फा. सं. 1/21/26/2016-मंत्रि.]

दीप्ति उमाशंकर, संयुक्त सचिव

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th January, 2017.

S.O. 313(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:-

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) Three Hundred and Thirty First Amendment Rules, 2017.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, in the SECOND SCHEDULE,-

(a) under the heading "MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SAMAJIK NYAYA AUR ADHIKARITA MANTRALAYA)", under the sub-heading "A. DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SAMAJIK NYAYA AUR ADHIKARITA VIBHAG)", after entry 24, the following entry shall be inserted, namely:-

"25. Monitoring of Scheduled Castes Sub-Plan, based on the framework and mechanism designed by NITI Aayog.";

(b) under the heading "MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS (JANJATIYA KARYA MANTRALAYA)", after entry 9, the following entry shall be inserted, namely:-

"10. Monitoring of Tribal Sub-Plan, based on the framework and mechanism designed by NITI Aayog.";

(c) under the heading "NITI AAYOG (NATIONAL INSTITUTION FOR TRANSFORMING INDIA)", in entry 1, under item (i), after sub-item m, the following sub-item shall be inserted, namely: -

"n. (A) To design a framework and mechanism for monitoring of the Scheduled Castes Sub-Plan and Tribal Sub-Plan;

(B) To evaluate the Scheduled Castes Sub-Plan and Tribal Sub-Plan".

PRANAB MUKHERJEE

President

[F. No. 1/21/26/2016-Cab.]

DEEPTI UMASHANKAR, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.02.01 10:52:52 +05'30'